जयपुर में जोधपुर-रावत मिष्ठान भंडार की दुकानों पर छापा

पैकिंग डिब्बों पर नियमानुसार जानकारी नहीं मिली, जुर्माना लगाया



जयपुर,वेब वार्ता । में फेमस जोधपुर और रावत मिष्ठान की दुकानों पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान पैकिंग बॉक्स और पैकर पर जरूरी जानकारी अंकित नहीं होने पर दोनों के खिलाफ जुर्माना लगाया।

मिठाई, नमकीन पैक करने वाले पैकेटों पर अंकित नहीं मिली जानकारी

उपभोक्ता मामल विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ टीम को खातीपुरा मोड़ क्वींस रोड स्थित जोधपुर मिष्ठान्न भंडार पर विजिट पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। इसके अलावा मिठाई, नमकीन पैक करने वाले पैकेटों पर नियमानुसार जानकारी अंकित नहीं मिली। इस पर संबंधित पैकेट जब्त कर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

रावत मिष्ठान्न भंडार के जयपुर स्थित अलग-अलग आउटलेट्स पर कार्रवाई की। गौरव टावर मालवीय नगर स्थित स्टोर पर ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैकेटों पर जरूरी जानकारी अंकित नहीं मिली। पैकर रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला। इसके चलते इस स्टोर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

नोटिस जारी, जुर्माना लगाया

इसी तरह पोलीविक्ट्री आउटलेट पर मिक्चर नमकीन, गजक और मठरी के पैकेटों पर और महल रोड जगतपुरा आउटलेट पर मिठाई के पैकेटों पर जरूरी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद दोनों संस्थाओं को नोटिस जारी किया।

इसके अलावा टीम ने निर्माण नगर अजमेर रोड स्थित अरहम स्वीट्स पर भी विजीट की। यहां पैकर पंजीकरण और पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएं नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया।

सिरोही में विद्यार्थियों ने लिया ईमानदारी का संकल्प

भाषण प्रतियोगिता के विजेता पांच विद्यार्थियों को पुरस्कार मिले

सिरोही, 28 अक्टूबर (का.सं.)। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सिरोही बिजनेस ऑफिस की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन, नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी पर विचार रखे।

प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पांच विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप में पेन वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार उन्मूलन की शपथ दिलाई गई।

भ्रष्टाचार मुक्त समाज में युवाओं की भूमिका पर जोर

क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी सुशील गुप्ता के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य



विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना और ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा देना था। साथ ही, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े विचार साझा किए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले पांच विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। अन्य प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें पेन भेंट किए गए।

ईमानदारी और निष्पक्षता से कर्तव्य निभाने का संदेश

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और निष्पक्षता से करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई।

सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग रहने का संकल्प

कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को सत्यनिष्ठा एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन की शपथ दिलाई गई।

जेल में कैदियों को तंबाकू पहुंचा रहा था प्रहरी

हेड कॉन्स्टेबल ने सबूत मिटा कर दबाया मामला, दोनों के खिलाफ सूरजपोल थाने में केस दर्ज

उदयपुर, 28 अक्टूबर (का.सं.)। उदयपुर सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों के लिए प्रतिबंधित सामग्री (तंबाकू) ले जाने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दो जेल कर्मियों, प्रहरी पंकज कुमार और आरएसी के हेड कॉन्स्टेबल गिरधारी सिंह के खिलाफ सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के बाद दोनों की कथित मिलीभगत उजागर हुई। मामले ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हेड कॉन्स्टेबल ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया

जांच में सामने आया कि हेड कॉन्स्टेबल गिरधारी सिंह ने इस मामले को दबाने के लिए आरोपी प्रहरी पंकज कुमार के साथ मिलीभगत कर ली। गिरधारी सिंह आरोपी प्रहरी पंकज कुमार को जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे की नजरों से हटाकर किनारे बने तलाशी कक्ष में ले गया। वहां पंकज की वर्दी से मिली तंबाकू को जब्त करने और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बजाय दोनों ने कथित तौर पर उसे नष्ट कर दिया। आरोप है कि तंबाकू जेल के अंदर कैदियों तक पहुंचाई जानी थी। इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

अपराध नहीं, हिमाचल हाई कोर्ट ने समयसीमा बीतने पर खारिज किया केस

शिमला,वेब वार्ता । हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक के बाद पति या उसके परिवार के पास स्त्रीधन का बकाया रहना एक 'निरंतर अपराध' नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कानूनी रूप से पति-पत्नी का रिश्ता खत्म होने के बाद पत्नी को तीन साल की निर्धारित समयसीमा के भीतर ही स्त्रीधन की वापसी के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करवानी होगी। यह फैसला न्यायाधीश चिराग भानु सिंह ने आरोपित पूर्व पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन और आरोप पत्र सहित पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद कर दिया है।

एक साल बाद ही हो गए थे अलग: पीड़ित महिला और याचिकाकर्ता की शादी साल 2007 में हुई थी, लेकिन विवाद के कारण वे 2008 से ही अलग रहने लगे थे। पूर्व पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर अदालत से नौ अक्टूबर 2012 को तलाक की एकतरफा डिक्री हासिल कर ली थी। तलाक के करीब पांच साल बाद महिला ने 19 जुलाई 2017 को शिमला के ट्रायल कोर्ट में आरोप लगाया कि उसका स्त्रीधन अभी भी पूर्व पति के पास है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि न्यायिक अलगाव में पति-पत्नी का कानूनी रिश्ता बना रहता है, इसलिए वहां स्त्रीधन रोकना एक निरंतर अपराध माना जा सकता है। लेकिन तलाक की डिक्री मिलते ही दोनों का कानूनी रिश्ता टूट जाता है।

जयपुर में लगेगी देश की पहली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर-स्तरीय सोडियम-आयन बैटरी प्रणाली



जयपुर,वेब वार्ता । राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और विद्युत वितरण नेटवर्क को अधिक कारगर बनाने की दिशा में जयपुर डिस्कॉम ने महत्वपूर्ण पहल की है। जयपुर विद्युत वितरण निगम और ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक संस्था ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (जी-ऐप) के बीच देश की पहली वितरण ट्रांसफॉर्मर स्तर की सोडियम-आयन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की पायलट परियोजना विकसित करने जा रहे हैं। विद्युत वितरण निगमों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन इन दोनों संस्थाओं ने इसके लिए जयपुर के के.एल. सैनी स्टेडियम में 250 किलोवाट/250 किलोवाट-घंटा क्षमता की पायलट परियोजना को विकसित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रण (आरएफपी) जारी किया। इस परियोजना के माध्यम से जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में विद्युत की अधिकतम स्थानीय मांग का प्रबंधन करने तथा रूफ टॉप सोलर से उत्पादित बिजली का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में सोडियम-आयन बैटरी तकनीक की क्षमता का आकलन किया जाएगा। परियोजना के तहत वितरण ट्रांसफॉर्मर के स्तर पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित कर यह आकलन किया जाएगा कि उपभोक्ताओं के नजदीक बैटरी एनर्जी भंडारण सिस्टम स्थापित करने से ट्रांसफॉर्मर पर अधिकतम विद्युत मांग के दौरान निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में कितनी सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही लिथियम-आयन जैसी प्रचलित बैटरी तकनीकों के विकल्प के रूप में सोडियम-आयन तकनीक की उपयोगिता भी परखी जाएगी। इसके अनुसार जयपुर डिस्कॉम परियोजना के लिए स्थान, तकनीकी कार्मिक और संचालन संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराएगा। वहीं, ग्लोबल एनर्जी एलायंस प्रणाली के डिजाइन, प्रदर्शन की निगरानी और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ डिस्कॉम के अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दोनों संस्थाएं परियोजना के निष्कर्ष एवं परिणामों को साझा करेंगी, ताकि देश की अन्य विद्युत वितरण कंपनियां भी अपने नेटवर्क में सोडियम-आयन ऊर्जा भंडारण प्रणाली की उपयुक्तता का आकलन कर सकें। इस पहल पर शासन सचिव ऊर्जा एवं राजस्थान डिस्कॉम्स की अध्यक्ष सुश्री आरती डोगरा ने कहा कि पीक समय में जैसे ही बिजली की मांग बढ़ती है। विद्युत तंत्र पर उसका सबसे प्राथमिक असर वितरण ट्रांसफॉर्मर के स्तर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यह पायलट परियोजना प्रदेश के वितरण नेटवर्क को कारगर बनाने, रूफ टॉप सोलर से उत्पन्न सौर ऊर्जा को भंडारित करने और यहां की जलवायु परिस्थितियों में यह परीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगी कि लिथियम-आयन के विकल्प के रूप में ऊर्जा भंडारण तकनीक इस दबाव को कम करने में कितनी प्रभावी हो सकती है। परियोजना से प्राप्त अनुभव भविष्य में विद्युत वितरण नेटवर्क में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की स्थापना से संबंधित अधिक विश्वसनीय निर्णय लेने में सहायक होंगे। ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट की कंट्री हेड तान्या सिंघल ने कहा कि आने वाले समय में भारत के विद्युत ग्रिड में ऊर्जा भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और विद्युत वितरण कंपनियों के पास चयन के लिए एक से अधिक विश्वसनीय बैटरी तकनीकों के विकल्प होने चाहिए। राजस्थान की परिस्थितियों में कार्यरत ट्रांसफॉर्मर पर सोडियम-आयन तकनीक का परीक्षण विद्युत वितरण कंपनियों को अनुमानों के बजाय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगा। उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के साथ इस पहल को आगे बढ़ाने और इससे प्राप्त अनुभवों को देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों के साथ साझा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। नेटवर्क स्तर पर प्राप्त जानकारी और उभरती ऊर्जा भंडारण तकनीक के वास्तविक परीक्षण को एक साथ लाने वाली यह परियोजना भारत में विकेन्द्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों तथा विद्युत वितरण ग्रिड के आधुनिकीकरण से संबंधित भविष्य के निर्णयों के लिए व्यावहारिक एवं प्रमाण-आधारित जानकारी उपलब्ध कराएगी। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है, जो स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक अवसरों को गति देने के लिए सार्वजनिक, निजी और परोपकारी संस्थाओं के बीच साझेदारी विकसित करती है।

इंदौर में कारोबारी से 80 लाख वसूलने के बाद एक करोड़ की मांग, सरोगेट मदर गिरफ्तार

इंदौर,वेब वार्ता । शहर के एक प्रापर्टी कारोबारी को एक करोड़ रुपये के लिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार, वह कारोबारी से पहले 80 लाख रुपये वसूल चुकी है। एडिशनल डीसीपी दीशेष अग्रवाल के अनुसार, कारोबारी की पत्नी कृतिका तलरेजा ने राजमहल कालोनी निवासी महिला के खिलाफ शिकायत की। कृतिका और उनके पति संतोष तलरेजा की एक बेटी है, जो स्पेशल चाइल्ड है। कृतिका दोबारा मां नहीं बन सकती थीं, इसलिए दंपती ने आरोपित महिला से सरोगेट मदर बनने के लिए बात की थी। सरोगेसी से पहली बेटी हुई, लेकिन महिला ने उसे देने से मना कर दिया। दूसरा बेटा होने पर उसे भी अपने पास रख लिया। महिला ने बच्चों के लिए फ्लैट और एफडी भी करवाई। वह विवाहित है और पति के साथ रहती है। उसने पति से जन्मी बेटी को भी संतोष का नाम दे दिया। आरोप है कि महिला ने संतोष का कारोबार देखकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2019 में उसने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई और बाद में समझौता कर लिया।



इसके बदले उसने अपनी बेटी को संतोष का नाम देने की शर्त रखी। शिकायत में कहा गया है कि महिला अब तक संतोष से 80 लाख रुपये वसूल चुकी है और एक करोड़ रुपये मांगकर दंपती को धमका रही है। वह घर आकर बदनाम करने और कालोनी में बेइज्जत करने की धमकी देती है। उसके पास संतोष के आपत्तिजनक फोटो भी हैं।

सूखाग्रस्त नांदेड़ में 200 विद्यार्थियों को नीट, जेईई की मुफ्त कोचिंग



नांदेड़,वेब वार्ता । महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त नांदेड़ जिले में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों के 200 मेधावी विद्यार्थियों को नीट, जेईई और सीईटी प्रवेश परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। जिला प्रशासन ने उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विद्यार्थियों की मदद के उद्देश्य से यह पहल की है। जिला प्रशासन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के जिला परिषद हाई स्कूलों और निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों का चयन दिसंबर में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उदयपुर-जयपुर इंटरसिटी में अब होंगे 22 डिब्बे

30 अक्टूबर से बदलेगी व्यवस्था, चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को मिलेगा फायदा

चित्तौड़गढ़, 28 अक्टूबर (का.सं.)। उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस (12991/12992) में 30 अक्टूबर से नई कोच व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद ट्रेन कुल 22 डिब्बों के साथ चलेगी। नई व्यवस्था में एसी, चेयर कार और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे। इससे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अलग-अलग श्रेणियों में यात्रा करने का विकल्प मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन की नई कोच संरचना 30 अक्टूबर से लागू की जाएगी।

ट्रेन में होंगे 22 डिब्बे

नई व्यवस्था के तहत इंटरसिटी एक्सप्रेस में 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 3 एसी चेयर कार और 1 थर्ड एसी इकोनॉमी कोच होगा। इसके अलावा 7 सेकंड सिटिंग चेयर कार, 5 जनरल कोच, 1 पावर कार और 1 गार्ड कोच शामिल रहेगा। इस तरह ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे। नई कोच व्यवस्था से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार कोच चुनने का विकल्प मिलेगा।

चित्तौड़गढ़ किले पर शराब-पार्टी रोकेगा ड्रोन, MP की कार जब्त

घने जंगल में भी हो सकेगी पेट्रोलिंग, एसपी बोले- टूरिस्ट को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी

चित्तौड़गढ़, 28 अक्टूबर (का.सं.)। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अब पुलिस ने ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की है, ताकि सुनसान इलाकों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस नई व्यवस्था का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि दुर्ग घूमने आने वाले हजारों पर्यटकों को सुरक्षित माहौल देना भी है।



पुलिस का कहना है कि परिवार, महिलाएं और बच्चे बिना किसी परेशानी के पूरे किले में घूम सकें। इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन की मदद से उन जगहों तक भी निगरानी पहुंच रही है, जहां सामान्य पुलिस गश्त हर समय संभव नहीं हो पाती। अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध एमपी नंबर की कार को जब्त किया और इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी।

72 मिनट तक हुई निगरानी, कई इलाकों पर रखी नजर

कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की ड्रोन टीम ने दो अलग-अलग उड़ानें भरकर कुल 72 मिनट तक निगरानी की। इस दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलग-अलग हिस्सों के साथ शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर भी नजर रखी गई।

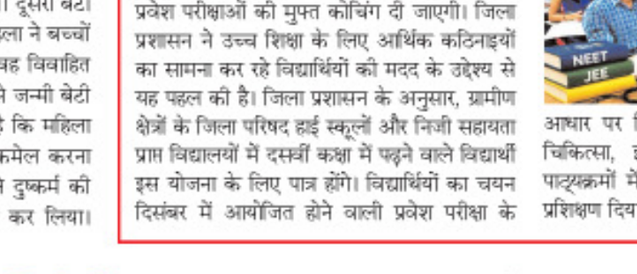
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों की आवाजाही कम रहती है। इन्हीं सुनसान स्थानों का फायदा उठाकर कुछ लोग शराब पार्टी करते हैं और नॉनवेज बनाते हैं। दुर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कई बार पुलिस और प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी। खास बात यह है कि कुछ धार्मिक और पवित्र स्थलों के आसपास भी इस तरह की गतिविधियों की सूचना समय-समय पर मिलती रही है।

केरलम मर्सिडीज हादसा: भारी दबाव के बाद एक्शन में सरकार, जज के खिलाफ FIR दर्ज

कोच्चि,वेब वार्ता । केरलम में एक जज के नाबालिग बेटे द्वारा चलाई गई मर्सिडीज-बेंज कार की दुर्घटना में 55 वर्षीय जयबालाकृष्णन की मौत के मामले में पुलिस जांच में खामियों को स्वीकार करते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कार के मालिक जज के खिलाफ भी एफआईआर में धारा जोड़ी गई है और चार पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला के निर्देश पर मंगलवार को एफआईआर में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए जोड़ी गई, जिसके तहत नाबालिग के अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। धार निलंबित पुलिसकर्मी हैं, सर्कल इंस्पेक्टर श्याम कुमार केएस, सब-इंस्पेक्टर विश्वजीत, ग्रेड सब-इंस्पेक्टर मनोज केटी और सिविल पुलिस अधिकारी अरुण जोशी। परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जज और उनके 17 वर्षीय बेटे का पक्ष लिया। नाबालिग ने मर्सिडीज से स्कूटर सवार जयबालाकृष्णन को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि शुरुआती एफआईआर में उचित धाराएं नहीं जोड़ी गई और आरोपी को रात में ही जमानत दिलाने की जल्दबाजी की गई। गृह मंत्री चेन्नीथला ने विधानसभा में कहा कि जांच में खामियां हुईं और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दोहराया कि जज को भी कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस को नाबालिग की जमानत रद्द करने के लिए सत्र न्यायालय जाने का निर्देश दिया गया है। एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) पी. विजयन कोच्चि पहुंचे और परिवार की शिकायतों की जांच की।

कर्नाटक एमएलसी चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, चारों सीटों पर जीता भाजपा-जेडीएस गठबंधन

बेंगलुरु,वेब वार्ता । कर्नाटक विधान परिषद चुनावों में राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। चुनावों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) के गठबंधन ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की है। कर्नाटक में 23 अक्टूबर को चार सीट पर हुआ विधान परिषद का चुनावों गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इस चुनाव के नतीजों में ये गठबंधन 100 प्रतिशत नंबर से पास हुआ है। कर्नाटक एमएलसी चुनाव परिणामों से सामने आया है कि शिक्षकों और स्नातकों के बीच कांग्रेस भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रही। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में दबदबा



कायम किया है। भाजपा ने उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की। वहीं, उसके सहयोगी दल ने बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज की। उत्तर-पूर्व शिक्षक सीट पर, दोबारा चुनाव लड़ रहे शशील जी. नमोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर को हराया। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नमोशी की पांचवीं जीत थी। इस सीट के अंतर्गत कलबुर्गी आता है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह क्षेत्र है। दक्षिण-पूर्व स्नातक सीट पर के.एम. सुरेश ने कांग्रेस के शशि हुलिकुंटे मुट्ठ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में के.एस.वी. संकानूर ने कांग्रेस के मोहन लिम्बिकाई को मात दी। चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सरकार की स्थिरता पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का मजबूत प्रदर्शन उसे 2023 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पर हमला करने के लिए कुछ गति जरूर देगा। 75 सदस्यों वाली विधान परिषद में कांग्रेस के 38 सदस्य हैं, 6, एक निर्दलीय सदस्य और एक सभापति हैं। सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित 5 सीटें अभी खाली है।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना
ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, परिशिष्ट हिंद (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालय- अर्श कॉम्प्लेक्स, ग्रंथिहत भवन, 22 तारदेव अमरी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट:- www.pnbhousing.com

रोशनी_बी.ओ. चित्तौड़गढ़: तीसरी मंजिल, दुकान नंबर 12, सी कल्याण कॉम्प्लेक्स, पन्ना धाय प्राइवेट बस स्टैंड के पास, गांधी नगर, मेन रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान-312001

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार "जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर" बेचा जाएगा। एतद्द्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आपी) (₹)	ईएमडी (10% या आपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मात्रिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ऑनलाइन/ऑफ लाइन/पीई पोर्टल (के)
एचओएल/आरसीएचआई/0523/1113503, कुन्दन कुन्दन/मंजू देवी, वी.ओ.: रोशनी_चित्तौड़गढ़	रु. 22,83,199.95 और 14/11/2024	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर 18, गांव सामरी, ग्राम पंचायत, तहसील, चित्तौड़गढ़, सामरी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान-312001, भारत।	रु. 16,20,000	रु. 1,62,000	12/11/2026	रु. 10,000	04-11-2026, 10:00 एएम- 5:30 पीएम	13.11.2026, 02.00 पीएम - 03.00 पीएम	ज्ञात नहीं है

*18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। * **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं। (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का जीर्णक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको पुष्पेंद्र सिंह, मो.:7976009512, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।

स्थान:- चित्तौड़गढ़ दिनांक:- 29.10.2026 एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Bandhan Bank

रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी ज